भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1986

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

कोकिंग कोयले के आयात में कमी

1986. श्री नीरज मौर्य:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्यिक कोयला खनन हेतु नीलामियों के पिछले चार दौर के पश्चात कोकिंग कोयले के आयात में दर्ज प्रतिशत कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू इस्पात उद्योग की उत्पादन लागत प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से इस्पात क्षेत्र के लिए मिशन कोकिंग कोल के अंतर्गत घरेलू धोवन क्षमताओं के आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अपनाए गए राजस्व-साझेदारी मॉडल से उत्पन्न आय को किस प्रकार प्रभावित स्थानीय समुदायों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला खान नीलामी के माध्यम से वाणिज्यिक कोयला खनन वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। नीलामी का 10वां दौर दिसंबर 2024 में शुरू किया गया था और 13वां दौर अगस्त 2025 में शुरू किया गया था। वर्ष 2024-25 के दौरान कोकिंग कोल का आयात 57.58 मिलियन टन था और यह पिछले वर्ष की तुलना में 2.10 प्रतिशत कम था।

(ख) : इस्पात उद्योग को बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी के कोकिंग कोयले की आवश्यकता होती है, जो ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। भारत के पास इस विशिष्ट

प्रकार के कोयले का सीमित भंडार है जिसके परिणामस्वरूप मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जाता है, जो वैश्विक मूल्य में उतार-चढ़ाव के अधीन हो सकता है। हालांकि, इस्पात संयंत्रों में स्टाम्प चार्जिंग बैटरी प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित करने से घरेलू कोकिंग कोल का सम्मिश्रण संभव हो पाता है। इस्पात उत्पादन में घरेलू कोकिंग कोयले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कोयला मंत्रालय गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी (इस्पात-कोकिंग उप-क्षेत्र) के तहत इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोल लिंकेज प्रदान करता रहा है। इसके अतिरिक्त, कोयले की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के माध्यम से की जाती है और खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल विंडो मोड-एग्नोस्टिक (एसडब्ल्यूएमए) नीलामियों के माध्यम से कोयले की पेशकश की जाती है।

(ग) : मिशन कोकिंग कोल के तहत बीसीसीएल और सीसीएल की पुरानी वाशरीज के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण की स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	सहायक कंपनी	वाशरी	वर्तमान स्थिति
i	सीसीएल	राजरप्पा वाशरी	नवीकरण का काम पूरा
ii	बीसीसीएल	मूनिडीह कोल वाशरी	वास्तविक प्रगति: 91.00% वित्तीय प्रगति: 89.60%
iii	बीसीसीएल	मधुबन वाशरी	बीसीसीएल में नवीकरण के लिए अनुमान तैयार किया जा रहा है
iv	सीसीएल	केडला वाशरी	सीसीएल में नवीकरण के लिए प्रस्ताव अनुमोदनाधीन है

(घ) : राजस्व-हिस्सेदारी मॉडल के तहत, कोयला ब्लॉक आवंटन से प्राप्त राजस्व का हिस्सा संबंधित राज्यों को प्राप्त होता है। प्रभावित स्थानीय समुदायों के विकास सहित ऐसे राजस्व के उपयोग का निर्णय राज्य सरकार द्वारा अपनी बजटीय प्रक्रियाओं और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार लिया जाता है।

*****